

AN HON. MEMBER: How can a telegram be signed?

MR. SPEAKER: I tell you I might have been taken astray because sometimes when you speak in a private club, sometimes in a social circle, you do some loud thinking.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You are the guest speaker as Speaker of Lok Sabha and not in your personal capacity.

MR. SPEAKER: In my house, social circle or a club, I am not a Speaker. I have given you the gist of what I spoke.

PROF. MADHU DANDAVATE: I suggest that once you have made a categorical statement, the matter should be dropped.

And I may inform you that Mr Piloo Mody yesterday said that he has no objection to one-party system provided it is BLD.

SHRI PHLOO MODY (Godhra): He has distorted what I said.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I cannot throw it into the waste paper basket. He says 'I am hopeful of securing conclusive evidence'.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एक बार आप ने इन्फार्म कर दिया मामला खत्म हो जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि यह मामला बार बार उठे।

श्री मधु लिमये : आप मुझे अब प्रागे वढो दीजिए।

PROF. MADHU DANDAVATE: The matter should be ended now.

Let us take up the next item, Sir.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It was most unwise to quote Prime Minister of Zambia. He has no locus standi.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जम्बिया के प्राइम मिनिस्टर को कट्रोवर्गी का मैटर इस हाउस में मत बनाइए।

MR. SPEAKER: I said exactly what had been said there. They have

already given that out. I am so sorry, if even on an academic question, or academic discussion. I should be debarred from expressing myself; tomorrow for instance, if I talk of Gandhiji or Marx or Engels or some other modern writers, and motives are attributed. God help!

Now, Shri Madhu Limaye.

12.22 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

IMPORT LICENCES CASE

श्री मधु लिमये (बाँका) : अध्यक्ष महोदय, आपने तुलसीमोहन राम वाले मामले को उठाने की मुझे अनुमति दी है। तुलसीमोहन राम वाले लाइसेंस स्कैण्डल के बारे में इस मदन को आश्वासन दिया गया था कि सी० बी० आर्टी० को जांच पूर्ण होने के बाद सारी जानकारी मदन को दी जाएगी, लेकिन लोक सभा बुलेटिन में तुलसीमोहन राम की गिरफ्तारी और जनाना पर गिराई के अलावा इस मदन का आगे कोई जानकारी नहीं दी गई। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मदन की गृह मंत्री जी ने जो वचन दिया था उन वचन के विपरीत क्यों काम किया गया है ?

दूराग मुदा—इस सभा को आश्वासन दिया गया था कि लाइसेंस काण्ड के सभी पहलुओं का पूरी जांच की जायेगी। आप को याद होगा—28 अगस्त, का हॉ, यानी जिस दिन उस मामले को हम ने मदन में उठाया था, उसी दिन मैंने जानकारी दी थी कि इण्डो-बंगला देश ट्रेडिंग कार्पोरेशन और उन के श्री सिद्धीकी इन लाइसेंसों को बेचने के काम में लगे हुए हैं। मैंने 28 अगस्त को यह जानकारी दी थी, लेकिन इस के पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है, तकरीबन डेढ़ महीने के बाद इण्डो-बंगला देश ट्रेडिंग कार्पोरेशन के कार्यालयों पर और उन के निवास-स्थानों पर छापा मारे गये।

इसी बीच मे व्यापार मन्त्री को मैंने दो पत्र लिखे थे। इस लिए इस बात की सफाई भी होनी चाहिए कि जब 28 अगस्त को मैंने इन्डो-बंगला देश ट्रेडिंग कार्पोरेशन और इन लाइसेंसों के बारे में जानकारी दी थी तो छेड़ महीने तक सी० बी० आई० और सरकार की इसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों द्वारा कयो कार्यवाही नहीं की गई—इस की सफाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा मुद्दा यह है कि कामर्स मंत्रालय के कंट्रोल आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स इन लाइसेंसों की एप्लीकेशन की जांच करने के लिए पाण्डिचेरी, यनाम और माहे गये थे और उम दौरे में निश्चित रूप से उन को यह पता चला था कि ये कोई इन्स्टीट्यूट इम्पोर्टर्स या जेनरल पार्टीज नहीं है, ये बिल्कुल बोगस पार्टीज है और 19 माल और 15 माल के बाद इन के लाइसेंस के बारे में आर्डर पाम किये जाते हैं। ये जो कंट्रोलर है—ये था ललित नारायण मिश्र में लेकर प्रो० चट्टोपाध्याय तक जो व्यापार मन्त्री रहे, इन के बीच में एक बड़ी के रूप में काम करने रहे। इस लिए मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक उम अफसर को, जिन का नाम पिन्ने है, मन्पेण्ड कर के उन के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

मेरे 30 सितम्बर के पत्र के उत्तर में 31 अक्टूबर को व्यापार मन्त्री से एक पत्र मझे मिला, उस में कहते हैं—

"As regards the delay in replying to your letter, I was out of the country for a number of days, and, besides, certain consequential action had to be taken on receipt of interim reports, mainly from the CBI."

यह बहुत सिग्नलिकेन्ट बात है, इस का मतलब है कि सी० बी० आई० ही नहीं, अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की रिपोर्टें भी आई हैं, जिनकी जानकारी हम को नहीं दी गई है।

"The information sought by you in your letter of the 30th September, 1974, is therefore, being given at the earliest possible opportunity"

मैंने इम्पोर्ट कंट्रोलर के बारे में भी पूछा था—ये आगे कहते हैं—

"It is correct that officers of the Import Trade Control Authority visited Pondicherry to make on the spot study. You are also aware that CBI is enquiring into these matters and their report is awaited. On receipt of the report such action as may be considered necessary will be taken."

इस लिए अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहता हूँ कि इम्पोर्ट कंट्रोलर के बारे में आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इन्होंने पाण्डिचेरी जाने के बाद कौन सी रिपोर्ट सरकार की दी थी, उम में इन तथ्यांकित इन्स्टीट्यूट इम्पोर्टर्स को लाइसेंस देने के बारे में कौन सा जस्टीफिकेशन दिया गया था। जब कि वास्तविकता यह है कि ये पार्टीज इतनी बोगस है कि इन के नाम से जो 28 लाख रुपये का लाइसेंस इन को मिला था, ये उम का माल मगवाने की स्थिति में भी नहीं है, इस में इन की बॉमेसिटी और ज्यादा जाहिर हो जाती है। इसलिए मेरी मांग है कि सी० बी० आई० तथा अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की जिनकी रिपोर्टें हैं, उन की कापिया इस सदन के सभा पटल पर रखनी चाहिए।

साथ ही साथ तुलसीमोहन राम के बारे में मैंने नियम सं० 184 के तहत एक प्रश्नाय भी दिया था, लेकिन आप का कार्यालय मझे सूचित करता है कि जा यूजअल प्रोसीजर है उस को आग फॉलो कीजिए। यानी यह प्राइम मिनिसटर के पास जायेगा और उस के बारे में सबूत दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सारी सूचनाये आप के सामने हैं, रोजाना

[श्री मधु लिमये]

अखबारों में रिपोर्ट छप रही है, फिर भी आप का कार्यालय कह रहा है कि तुलसीराम को लिए जा आप का प्रस्ताव है उस के लिए इस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर फॉलो कीजिए। वह कौन सा प्रोसीजर है, इस पर मैं आप की सलाह चाहता हूँ।

मेरे प्रस्ताव में यह कहा गया है —

'That this House resolves that Shri Tulmohan Ram who had made false statements after the prorogation of Lok Sabha and found guilty of receiving gratification and other misdemeanours be removed from the membership of the House'

उस के साथ साथ मैंने एक दूसरा प्रस्ताव भी दिया था कि इन सभी रिपोर्ट्स के आधार पर आप पार्लियामेन्ट्री कमेटी नियुक्त करने की जो हम लोगों की मांग है उस को मान लीजिए क्योंकि गृह मंत्री जी ने खद कहा था कि हम पार्लियामेंट के अधिकारों को नहीं छीनना चाहते हैं, तबिन सी० पी० आई० का रिपोर्ट मान के बाद हम लोगों को मारा देगे। अध्यक्ष महोदय अगर पार्लियामेन्ट्री कमेटी नहीं रैटनी है तो श्री ललित नागायण मिश्र प्रा० चट्टोपाध्याय और इन के बड़े बड़े अफसरों का जो इस लाइमेस काण्ड में हाथ रहा है उस का रहस्य-विस्फोट हम लोग भी कर पायेंगे। यह काम सी० पी० आई० ग हाँने वाला नहीं है। अखबारों में हम ने पढ़ा है—सी० पी० आई० का तो यह कहना है कि 20 सदस्यों के हस्ताक्षर स्वयं तुलसीराम और उनके साथियों ने फौज किये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) नहीं नहीं

श्री मधु लिमये : अखबारों में यही आया है कि उन्होंने फौज किया है। मैं

जानना चाहता हूँ—क्या सी० पी० आई० इसी तरह के सर्टिफिकेट देता जायगा? मैं आप को श्री काननगो के पत्र के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ—सी० पी० आई० के जो हैण्ड-राइटिंग एक्सपर्ट—श्री गुप्ता थे, उन्होंने प्रदालन में यह सलाह दी थी कि श्री काननगो के सिगनेचर फोज्ड है, लेकिन बाद में क्राम-एक्जामिनेशन में वे कोलेस हो गये और उन्होंने स्वीकार किया कि सिगनेचर जैनुइन है। इस लिए सी० पी० आई० के एक्सपर्ट की बान चलने वाली नहीं है। आज अखबारों में खबर छप रही है कि 6-7 सदस्यों के हस्ताक्षर जैनुइन है। इस लिए पार्लियामेन्ट्री कमेटी नियुक्त कर के हम को इण्डीपेण्डेंट हैण्डराइटिंग एक्सपर्ट को बुलान का मौका मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब तक पार्लियामेन्ट्री कमेटी नियुक्त नहीं होगी, तब तक इन लोगों के बारे में शक बना रहेगा और यह स्थिति भसद की गरिमा के बारे में अच्छी नहीं है। इस लिए उन साठे सदस्यों को मैंने आप के सामने रखा है और आप से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रस्तावों को आप अवश्य स्वीकार करें। मेरे उन दोनों प्रस्तावों पर यथा बहस होनी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (भ्यालियर) अध्यक्ष जी, आज फिर सदन में लाइमेस काण्ड की गुंज सुनाई दे रही है। पिछले अधिवेशन में जब यह मांग की थी मैंने एक प्रस्ताव दे डाला कि श्री तुलसीराम को सदन की सदस्यता से निलम्बित कर दिया जाय तो गृह मंत्री महोदय ने कहा था कोई प्राइमफेसी केस नहीं है जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष जी, कार्यवाही में इतनी देर हुई यह तो एक आम शिकायत का विषय है, लेकिन जब इस सदन के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया तो मतलब यह है कि

प्राइमफेसी केस है। अब सदन की नेत्री, प्रधान मंत्री, श्रीमती बिहारी गांधी, मदनल केस के अनुसार श्री तुलमोहन राम के विरुद्ध प्रस्ताव क्यों नहीं ला रही है ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, I rise on a point of order, I want to know is he speaking on privilege motion?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं भी प्रिविलेज पर ही बोल रहा हूँ।

MR. SPEAKER: Before me on a motion of privilege, three names are given I have got three names under one heading. When I say his, I mean, Madhu Limaye's.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी श्री तुलमोहन राम के विरुद्ध प्रस्ताव लाने के लिए तैयार नहीं है ? मदन मदन के रूप में अब उन्होंने अपनी स्थिति का दुरुयोग किया, अपना पद लाभ उठाने के लिए प्रयत्न किया उन पर धोखाधड़ी का आरोप जालगाजी का आरोप है। क्या यह सारे मामले इस बात का तकाजा नहीं करते कि उन के विरुद्ध सदन कार्यवाही करे ? जो मामला सी० बी० आई० ने दाखिल किया है वह चलेगा, लेकिन संभव मदन के रूप में उन का आचरण इस सदन की भी निन्दा का और कार्यवाही का विषय बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, क्या लाइसेंस कांड के बारे में हमें सारी जानकारी समाचार-पत्रों से मिलेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सी० बी० आई० ने भी इस मामले में आप को अभी तक कोई जानकारी दी है ? जब सदन की प्राइमरी विज बैडक हो रही थीं तब मैं तो आप ने कहा था कि सी० बी० आई० को छूट दे रहा हूँ कि इस मामले के बारे में जिस को चाहे वह पूछताछ कर सकते हैं। उस समय हम ने कहा था सी० बी० आई० आप को भी जांच की शक्ति के बारे में जानकारी देती रहे। कल उन को एक बड़े गिरफ्तार किया गया, गृह मंत्री बीच में आ कर इन्तजाम दे सकते

थे अभी तक सी० बी० आई० जांच कर रही उस का क्या परिणाम निकला। कल, श्री जब समाचार-पत्रों ने पूरी जांच की रिपोर्ट मापी तो समाचार-पत्रों को दी नहीं गई। पिछले सेशन में भी हम को ऐफ० आई० आर० के बारे में पूरी तरह से विश्वास में नहीं लिया गया था। अगर आप को जानकारी नहीं दी गई है तो मैं कहूंगा गृह मंत्री जी एक अनौचित्य के दोषी है। भविष्य में हम समाचार-पत्रों से इस बारे में जानकारी प्राप्त करें यह सदन की गरिमा के लिए ठीक नहीं होगा। हमें गृह मंत्री से पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि सी० बी० आई० की जांच एक नतीजे पर पहुंची है और गृह मंत्री महोदय पिछले सत्र में कह चुके हैं कि अगर कोई बात निकलेगी, और विधि मंत्री महोदय भी कह चुके हैं कि मामला सदन के सामने आ जायगा और सदन जो फैसला चाहेगा वह करेगा। यह मामला कौन ले कर आयेगा ? विरोधी दल वाले लायेगे ? ऐफ आई आर की कौपी उन के पास है, सी० बी० आई० की रिपोर्ट उन के पास है, समाचार-पत्रों में छुटपुट खबरें छर रही हैं, सदन अंधेरे में है, हमारे पास पूरी जानकारी है हम यह दावा नहीं करते, और सरकार मौन बैठी है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोगों के नोटिसेब के अलावा क्या आप के पास गृह मंत्री का भी कोई पत्र आया है कि वह तुलमोहन राम के बारे में कोई बयान देना चाहते हैं ?

MR. SPEAKER: This morning they conveyed to me that they want to make a statement on this.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तुलमोहन राम का मामला हम ने कल ही उठाया था कि पकड़ लिये गये और बेल पर छोड़ दिये गये। आप को पता होगा प्राइमरी संत्री प्रो० चट्टोपाध्याय ने कहा था

[श्री प्रदल बिहारी वाजपेयी]

कि यह जो फर्म हैं जिन्हें लाइसेंस दिये गये हैं यह वास्तव में ठीक काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ला सभ के आधार पर उन्होंने माल मंगाया। जब यह पूछा गया कि उन्होंने लाइसेंस बेच दिये, उन्होंने माल नहीं मंगाया, सिर्फ कमीशन लिया है, तो वाणिज्य मंत्री ने कहा कि माल मंगाया गया है लाइसेंस बेचा नहीं गया। अभी आज अखबार से पता चलता है कि यह फर्म अस्तित्व में ही नहीं है, यह लाइसेंस ले कर दूसरी को दिया करती थी और मुनाफा कमाती थी। दूसरी फर्म माल मगाती थी। यह बात अगर सच है तो वाणिज्य मंत्री प्रो० चट्टोपाध्याय सदन को गुमराह करने के बोधी है। ऐसा उन्होंने क्यों किया यह उनको स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो उन के विरुद्ध हम प्रिविलेज इश्यू लायेंगे। यह सदन तभी अपना दिमाग बना सकता है जब सी० बी० आई० की जो रिपोर्ट अब तक की है उस को सदन के सामने रखा जाय और उस जांच के आधार पर प्रधान मंत्री श्री तुल मोहन राम के बिनाफ़ क्या कार्रवाही करने जा रही हैं यह भी सदन की बताया जाय। इस तरह से हम समाचार-पत्रों से खबरें प्राप्त करें यह सदन की गरिमा के लिए ठीक नहीं है। और मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। सारा मामला सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता।

SHRI JYOTIRMOY BOSU. Sir, I have given my privilege motion under Rule 223 because the Home Minister has deliberately committed a breach of privilege by allowing the C.B.I. Enquiry Report on the Licence scandal to go to the press without first placing it before this House violating his earlier clear and categorical promise and assurances given on the floor of the House.

While replying to the licence scandal debate, he said—I am quoting from the debate:

"I am making a promise. I am giving an assurance that after the investigation is over, the first thing that we will do is to come to Parliament and we will see this is where we have arrived. Please tell us what we should do. It is only after that according to the wishes to the Parliament, that we will proceed. We are not closing the door for further investigation by Parliament. There can be one remote possibility when the matter can go to the committee. As it is to-day, my request is that the matter should not be pressed."

Sir, he gave a clear and categorical assurance that once the C.B.I. has given its report, it will first come before the Parliament. The Home Minister undertook that responsibility of narrating the findings of the C.B.I. before the House before they may decide the course of action.

Now, instead of that, what they have done is that ten days prior to the commencement of the session or seven or ten days before, they gave it to the press. I have got the clippings from the Statesman—a double column given by Shri Kuldip Nayyar, who is a man of standing in the journalist world. Now, on the face of it, the C.B.I. has allowed this so called enquiry findings to the press which could well be seen in the newspapers for instance, the Statesmen etc. Furthermore the Government has prosecuted, without even informing the House, Shri Tul Mohan Ram, a sitting Member of the House and has arrested him along with some other persons. All these have been done within ten days prior to the commencement of the winter session.

This has been done by Government in clear violation of an undertaking, denigrating the House and committing a serious breach of privilege thereby, at a time when the session was practically knocking at their door. This is a

clear case of breach of privilege and I would like the matter to be referred to the Privileges Committee.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Arising out of the remarks that have been made by some hon. members, may I draw your attention to a news item which has been circulated by the UNI, a very respectable news agency, which says that the approver in this case has already made a statement that several honourable members of Parliament have received lakhs of rupees in this manner? This is in *The Times of India* of today.

SHRI PILOO MODY (Godhra): Only from one party.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: This further widens and deepens the issues with which we have been grappling all the time. This is one aspect of the matter....

SHRI VIKRAM MAHAJAN (Kan-
gra): These are stray remarks. He is condemning a class as such by saying 'several MPs'. This is wrong. He must specify. Otherwise, he should not make a wild allegation. He must specify one. He should not read a thrash. (Interruptions).

MR. SPEAKER: He is not going into a stray matter. He has said that arising out of what has been said, he is saying this referring to what the approver in this case has said. This is related to that. That is why I allowed it.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I am not making any allegation. Then I would also like you to recall that when during the course of the discussion last session I had made a request to you that the FIR and other necessary information must be made available to us, you were pleased to say that had I informed you earlier, you would probably have been in a position to secure such necessary information for the House. After that, I wrote to the Lok Sabha Secretariat. The Lok Sabha Secretariat, after three or four reminders, was able to get for

me the FIR, after 1½ or 1¼ months of struggle. I would like to know what has been the reason for this kind of reluctance on the part of Government to part with necessary information, information which is very necessary for our functioning and for coming to certain decisions in this matter. If we are prevented from functioning in a proper manner by Government, it is for the custodian of the House to take notice of it.

Then so far as the two motions are concerned, it seems to me that one is a formal motion by the hon. member, Shri Madhu Limaye, and the other is probably a suggestion embodied in the form of a motion that action should be taken against one member, the hon. Shri Tulmohan Ram. But may I tell my hon. friends not to walk into the trap of the ruling party which wants that the matter should and after the termination of the membership of Shri Tulmohan Ram? We cannot countenance this. If Shri Tulmohan Ram's membership has to be terminated, it must be on the basis of the view taken by the House and not the view taken by the CBI. We will have to come to certain decisions about this.

So the case of Shri Tulmohan Ram must be remitted to the care of the Privileges Committee, because on the basis of available information, the hon. member, Shri Tulmohan Ram, has undermined the prestige of this House. He has lowered the dignity of the House. So it is a fit case for reference to the Privileges Committee and we should not allow the matter to end after there is a formal motion from the other side, which probably the other side is only too eager to bring forward for the termination of the membership of Shri Tulmohan Ram. The issues go much more beyond Shri Tulmohan Ram or any other person.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Mr. Speaker, Sir, you will remember that a discussion took place in this House. I then moved a motion that a committee consisting of 15 to 17 Mem-

[Shri S. M. Banerjee]

Members of Parliament should be appointed and it should go into the whole affair. Unfortunately, that motion was defeated by the brute majority over there. But I did realise at that time, and our premonition was correct, that a time will come when the CBI will submit a report on the whole matter and that Shri Tulmohan Ram is going to be punished for the offence. The matter is more serious and it deserves deterrent action also.

Shri Uma Shankar Dikshit, when he was the Home Minister, gave certain assurances already in this House. His portfolio has been taken away; whether that portfolio contained some of the important papers and who is keeping them, whether it is the Prime Minister or the Home Minister, I do not know. So, in this case, I would like you to appoint a committee of this House. You can appoint a committee of this House to go into this entire matter, so that it may elicit more information and elicit the truth. A committee of this House is a must, and that should be appointed.

Today's newspapers say that Shri Tulmohan Ram, Shri Yogendra Jha and Shri S. M. Pillai have been arrested. Another Pillai was involved, but he has not been arrested. Ordinarily, even for small faults a Government servant is suspended immediately, but this Pillai has not been suspended though he is a senior Government official. So, I request you to see that the Home Minister makes a statement and this privilege motion and the other motion which has been moved by my hon. friend, Shri Madhu Limaye, should be kept in abeyance, kept pending, till such time as you make up your mind about the appointment of the committee to which I have referred.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, a point of order. I have given a specific motion and my basis for that is the documentary evidence taken from the debate which shows that the Home Minister was under a clear obligation to come before the House with the report of the CBI finding and then

proceed against Shri Tulmohan Ram or do whatever the House decides about it. Instead, they have gone to the press and they have taken action against Shri Tulmohan Ram and company. (Interruptions) I want my motion to be dealt with as it should be.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): I want to know whether the Government has given you the report of the CBI, interim or final, before any action was proceeded with. Has it been done?

MR. SPEAKER: I have not got any

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Sir, there are two aspects of this question. One aspect is concerned with the House and the other is concerned with the Government. There is a situation in which Shri Tulmohan Ram has created a situation whereby the dignity of the House has been lowered. And it is your responsibility to initiate steps against Shri Tulmohan Ram; that is your responsibility, because he has lowered the dignity of the House and the privileges of the House. This is one aspect. We want to know from you what steps you are going to initiate, and in which way; he has lowered the dignity of this House and the privileges of this House. And that is your concern; it concerns the House.

The other aspect is one which concerns the Government. The Government is committed to this House that when the CBI enquiry is completed they will suo motu come out with a statement before the House. On the first day, it passed off. This is the second day they have not done anything. When my friend Limaye drew the attention of the House to the matter the Government is coming to make a statement, although they have taken steps against Tulmohan Ram. There is one aspect about you also. The Government made a commitment to this House and that has not been fulfilled by them because they have leaked out the news to the Press.

There also it is your responsibility to pull up the Government why they have failed you should initiate a committee to go into the whole matter. The whole thing boils down to this, it is your responsibility.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): In this regard I want to submit that the Government wants to take shelter under the plea that the matter is *sub judice* because they have charge-sheeted certain persons. They want to go back on the assurance given to the House that they would place all the papers here before they proceed against any particular individual. It appears that Mr. Tulmohan Ram is made a scapegoat and others who were a party to this scandal are going to be let scot free. All the papers should be laid before the House even before the Government makes a statement: the House should be shown all the papers.

MR. SPEAKER: I have seen the old record, it is not because I do not believe in what Mr. Bosu had quoted but because you asked me to see it again. The Home Minister at that time gave a categorical assurance on 9-9-1974: "I may give an assurance that after this investigation is over, the first thing that we will do is to come to Parliament and we will say: this is where we have arrived, please tell us what we should do."

It is your predecessor's words. I am quoting. I do not know what you will do. He said: "It is only after that, according to the wishes of Parliament that we will proceed. We are not closing the door for further investigation by Parliament. There may be one remote possibility that the matter can go to a committee." He has been guarded in this sentence. He said further: "It is therefore my request that the matter should not be pressed."

May I invite the attention of the hon. Home Minister to one thing? In the observations made by hon. Members, they have raised some points. If he has a readymade statement which

does not cover these points, you can revise that and you can come later.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have given a specific motion.

MR. SPEAKER: There are some other motions also.

SHRI PARIPOORNANAND PAI-NULI (Tehri-Garhwal): Earlier the hon. Home Minister Mr. Dixit had stated that he would take the House into confidence and everything would be placed before the House. I want to know whether the Home Ministry has released the news item which has appeared in the Press or did it get the news from its own sources.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI K. BRAHMANANDA REDDY): A request was made to permit me to make a statement during the course of the day. If you permit me, I will make a statement at about 5 P.M. today.

SHRI MADHU LIMAYE: It should cover all the points raised.

MR. SPEAKER: I thought he was going to make it just now. That is why I said it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of Order, Sir. I have given a specific motion based on documentary evidence. It is clear that they have not complied with the assurance given to this house. This is a *suo motu* statement; it has nothing to do with the privilege motion. How can you mix up things and make a mincermeat of the rules of procedure like this? I want my privilege motion to be placed before the House.

MR. SPEAKER: Let the minister make the statement first. Papers to be laid.